Interim Relief to Employees in Newspaper Industry

726. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether orders for payment of interim relief to employees in Newspaper industry have since been issued;

(b) if so, the details thereof with criteria of payment of different cadres of employees;

(c) whether such orders have been issued on representations from Newspapers employees or the Government felt for such payment on their own;

(d) if so, the details thereof, separately;

(e) whether Government in future would order for such payment of their own whenever the same becomes due; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) to (c) Do not arise.

(e) to (f) The matter is under consideration of the Government.

Less Sugar production in first quarter of 1996-97

727. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite good prospects of sugarcane yield, sugar production during first three months of current year 1996-97 has been comparatively less than that during corresponding period of last year (1995-96);

(b) if so, comparative figures of sugar production; and

(c) reasons for decline in sugar production and how far the credit crunch especially in respect of sugar cooperatives and other sugar manufacturers is responsible therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) The sugar year is reckoned from October to September. The production of sugar upto 31st December, 1995 during the current 1995-96 sugar year was 37.27 lakh tonnes as against 41.16 lakh tonnes during the corresponding period of last sugar year, 1994-95. The decline in sugar production during the first three months of 1995-96 sugar season was due to late start of crushing operations by the sugar factories. Production started picking up from January, 1996 and has reached 158.02 lakh tonnes as on 15th June, 1996 in the current season 1995-96 as against 140.49 lakh tonnes on the corresponding date of the last sugar season 1994-95.

आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को हुए घाटे

728. श्री राम जेठमलानी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि आठवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के घाटों में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो आठवीं योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान घाटे की कुल धनराशि कितनी थी और कितने उपक्रम घाटे में चल रहे थे;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितना घाटा हुआ और घाटे में चल रहे उपक्रमों की अनुमानित संख्या कितनी थी;

(घ) क्या उक्त औद्योगिक उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग में वृद्धि किये जाने के कोई प्रमाण हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने उपक्रमों ने अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि की है; और

(च) यदि हां, तो इस वृद्धि की औसत दर क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी नहीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 106 उद्यमों ने 4113 करोड़ रुपये का घाटा उठाया था। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 116 उपक्रमों द्वारा उठाया गया घाटा 5223 करोड़ रुपये था और वर्ष 1994-95 के दौरान 109 उद्यमों ने 4907 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(घ) से (च) जी हां। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले 33 विनिर्माणकारी उद्यमों के अंतर्गत 51 उत्पादनकारी एककों ने वर्ष 1992-93 की तुलना में अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि की थी। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले 35 विनिर्माणकारी उद्यमों के अंतर्गत 60 उत्पादनकारी उद्यमों ने अपने संस्थापित उत्पादन क्षमता के उपयोग में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा वृद्धि की है। विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्षमता उपयोग का उद्यम-वार तुलनात्मक विवरण 19.7.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 के खण्ड-1 के विवरण सं॰ 23 में दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

729. **श्री रामजी लाल:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में राज्य-वार ऐसे कितने-कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संविधान में कब तक संशोधन किया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री कलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर, सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण पूर्णतया राज्य का विषय है और चूंकि आरक्षण को प्रत्येक राज्य द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसलिए केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक श्रेणियों में उन व्यक्तियों की संख्या का रिकार्ड नहीं है जिन्हें राज्य-वार लाभान्वित किया है।

(ग) और(घ) यह मामला विचाराधीन है।

Excess Sugar Production

730. DR. D. VENKATESHWAR RAO:. Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there has been excess production of sugar during current calendar year and Government have been urged to give clearance for export of additional sugar;

(b) if so, whether Government have given the directive;

(c) the extent to which additional sugar will be exported;

(d) whether Indian sugar mills will begreatly relieved if exports are allowed;

(e) whether Government's decision to delay in fixing the levy price of sugar has affected sugar industry; and

(f) by when a final decision is likely to be taken?.

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Until the close of the sugar season 1995-96 it is not possible to say how much sugar will be exported.

(d) Yes, Sir.

(e) No, Sir. The ex-factory price of levy sugar is applicable retrospectively from the beginning of the sugar season.

(0 The ex-factory prices for 1995-96 season have already been notified on 14.5.1996.